

## संपादकीय

## पुजारी के लिए भगवान को करना पड़ा इंतजार आपके पचास मिनट ने सिस्टम की पोल खोल दी

*एयरपोर्ट पर विमान पचास मिनट तक रनवे पर खड़ा रहा। अंदर सौ से अधिक यात्री बैठे थे। बोर्ड पर टेकऑफ़ का समय सुबह 8:40 बजे दिख रहा था, लेकिन विमान हिला तक नहीं। यात्रियों ने कारण पूछा तो जवाब मिला, ऑपरेशनल रीजन। पचास मिनट बाद सच्चाई सामने आई कि एक वीआईपी म्यूमेंट के कारण विमान रोका गया था। विमान गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन सवाल रनवे पर ही रह गया।*

*हवाई यात्रा में आम यात्री के लिए नियम बेहद कठोर हैं। दो घंटे पहले पहुंचो, कतार में लगो, पहचान दिखाओ, सामान तौलवाओ, सुरक्षा जांच कराओ और गेट पर इंतजार करो। एक मिनट की देरी हुई तो जवाब मिलता है कि गेट बंद हो गया, टिकट बेकार है। यह अनुशासन सिर्फ आम यात्री के लिए है। दूसरी तरफ़ खास यात्री हैं, जिसके लिए पूरा रनवे रोक दिया जाता है। एयर ट्रेफ़िक कंट्रोल, पायलट, क्रू और सौ यात्रियों का समय एक व्यक्ति की घड़ी से बंध जाता है। यह दोहरा मापदंड ही इस घटना का सबसे बड़ा सच है।*

*इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प शब्द है, ऑपरेशनल रीजन। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को यही जवाब दिया। कितना सुविधाजनक शब्द है। न वीआईपी का नाम आता है, न देरी की जिम्मेदारी तय होती है। यह एक परा है, जिसके पीछे सब कुछ छिप जाता है। सच कहने में क्या हर्ज था कि एक माननीय के कारण विमान रोका गया है? लेकिन सच कहने से सवाल उठते हैं और जवाब देना पड़ता है। इसलिए ऑपरेशनल रीजन कह दो और मामला खत्म। किसी यात्री का इंटरव्यू छूट जाए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट छूट जाए या अगली फ्लाइट छूटने से हजारों रुपये का नुकसान हो जाए, तो क्या उसके लिए भी यही जवाब पर्याप्त है? जनता को देरी का वास्तविक कारण जानने का हक क्यों नहीं है?*

*हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता भगवान हैं और जनप्रतिनिधि उसके सेवक हैं। देश मंदिर है और सेवक उसके पुजारी हैं। लेकिन यहां नजारा उलटा है। भगवान विमान में पचास मिनट से बैठा है, परेशान है और अपनी घड़ी देख रहा है। पुजारी अभी रास्ते में है। भगवान इंतजार करेगा, क्योंकि पुजारी को देर हो गई है। यह कैसी सेवा है, जहां सेवक के लिए मालिक को इंतजार करना पड़े? सेवक को तो समय का पाबंद होना चाहिए, लेकिन यहां सेवक देर करता है और मालिक को सजा मिलती है। यही वीआईपी संस्कृति का अहंकार है, जहां नियम दूसरों के लिए हैं, अपने लिए नहीं।*

*यह मामला सिर्फ पचास मिनट की देरी का नहीं, व्यवस्था की सोच का है। हमने बड़े एयरपोर्ट बना लिए, आधुनिक विमान ले आए और डिजिटल बोर्ड लगा दिए, लेकिन मन के भीतर बना वीआईपी लार्डज नहीं तोड़ पाए। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। यदि आम यात्री की एक मिनट की देरी पर टिकट रद्द हो सकता है, तो किसी खास व्यक्ति को देरी पर सौ यात्रियों का समय बर्बाद क्यों हो?*

*यात्री क्या करे? उसकी मीटिंग छूट जाए, इंटरव्यू छूट जाए या कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए, तो क्या हुआ? वह तो भगवान है। भगवान को त्याग करना ही चाहिए। अगली बार हवाई यात्रा करें तो दो घंटे नहीं, चार घंटे पहले पहुंचिए और इंतजार कीजिए। क्या पता, इस बार पचास मिनट नहीं, दो घंटे इंतजार करना पड़े। आखिर आप भगवान हैं और भगवान को इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है!*

### आजकल

## सत्यापन के नाम पर अटका युवा भविष्य बारह हजार आधार और बारह हजार सवाल

प्रदेश में बारह हजार से अधिक युवाओं के आधार कार्ड का सत्यापन लंबित होना सामान्य प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। झाबुआ में सात सौ से अधिक, इंदौर में पांच सौ से अधिक और भोपाल में साढ़े चार सौ से अधिक आधार कार्ड सत्यापन के इंतजार में हैं। ये सभी युवा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जब उन्हें अपनी पहचान की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज आधार बैंक खाता खोलने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, नौकरी के लिए पंजीजन कराने, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में सत्यापन अटकने से युवाओं के अवसर प्रभावित होना स्वाभाविक है। आंकड़ों के अनुसार, दस हजार से अधिक मामले तहसीलदार स्तर पर और ग्यारह सौ से अधिक मामले नोडल अधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं। सवाल है कि सत्यापन में इतनी देरी क्यों हो रही है? जब पंजीयन के समय ही पते की जानकारी उपलब्ध होती है, तो स्थानीय स्तर पर समयबद्ध जांच की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? तकनीक के इस दौर में महीनों तक फाइलों का लंबित रहना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल जिले में अधिक मामले लंबित होना विशेष चिंता का विषय है। रोजगार के लिए पलायन और पते में अंतर जैसी परिस्थितियों को संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। वहीं, इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी सैकड़ों मामले अटके होना बताता है कि समस्या प्राथमिकता और निगरानी की भी है।

इस देरी से छात्रवृत्ति, रोजगार पंजीयन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन को सत्यापन की समयसीमा तय करनी चाहिए, सात दिन में प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी निर्धारित चाहिए और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर युवाओं को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलना चाहिए। झाबुआ से भोपाल तक प्रशासन को समझना होगा कि बारह हजार आधार का लंबित सत्यापन, बारह हजार युवाओं के अवसरों पर सवाल है। आधार केवल कार्ड नहीं, उनके भविष्य की राह का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

### तेलंगाना

के आदिलाबाद जिले के लक्काराम गांव की कहानी आज देश के कई गांवों के लिए प्रेरणा बन रही है। इस गांव के लोगों ने महीने का एक दिन तय किया है। उस दिन वे निजी काम छोड़कर उन कार्यों में जुट जाते हैं, जो पूरे गांव के लिए जरूरी हैं। कभी सड़क की मरम्मत होती है, कभी पानी की टंकी की सफाई, कभी जाम नाली खोली जाती है, कभी तालाब तैयार किए जाते हैं। कभी कभी खाली जमीन पर पेड़ लगाए जाते हैं। ग्रामीण खुद मिलकर सारा काम करते हैं। इस पहल का नाम संगठित श्रमदान है। सोच सीधी है, गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी विभागों का मुंह देखना जरूरी नहीं। लोग मिलकर जुटें तो कई समस्याएं वहीं निपट सकती हैं। एकलव्य फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुई लक्काराम को इस पहल से प्रेरित होकर जिले के 25 गांव इस मॉडल को अपना चुके हैं। गांव के अप्पाराव कहते हैं कि गांव तब मजबूत बनता है, जब लोग विकास को किसी और की जिम्मेदारी मानना छोड़ देते हैं। हर गांव में किसान क्लब यह तय करते हैं कि कौन-सा काम किया जाना चाहिए।

इस पहल के केंद्र में किसान क्लब हैं। यहां ग्रामीण खेती के साथ गांव की दूसरी समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। मासिक बैठकों में स्थानीय मुद्दों, उनके समाधान, सरकारी योजनाओं और आगामी श्रमदान की रूपरेखा तय होती है। यानी पहले यह तय किया जाता है कि गांव को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर उसी के लिए श्रम

लागाया जाता है। इन आयोजनों के गांव की नियमित प्रक्रिया बनाने की कोशिश हो रही है। स्थानीय निवासी तलारी अंजम्मा कहती हैं कि काम भले ही एक दिन का हो, लेकिन उसका फायदा उस दिन के बाद भी गांव को मिलता रहता है। गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं, सभी श्रमदान में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यह केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी का भी अभ्यास है। जब एक ही कतार में गांव के सभी लोग फावड़ा उठाते हैं, तो जाति और हैसियत की दीवारें टूटती हैं। सामूहिक श्रम भारतीय गांवों के लिए नई बात नहीं है। इस पहल की खासियत यह है कि पुरानी परंपरा को दोबारा जीवित कर गांव के विकास की नियमित व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। गांव की जिंदगी बड़ी परिवोजनाओं से ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी एकजुटताओं से भी बदलती है।

फाउंडेशन के ग्राम सहायक मॉडल के तहत गांव के युवा स्वयंसेवकों की भूमिका निभा रहे हैं। वे किसान क्लबों को मजबूत करने, गतिविधियों की निगरानी करने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा टिकाऊ खेती से जुड़े कार्यों में मदद करते हैं। इससे गांव में ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, जो पूरे हो चुके कामों को संभाल सकें और आगे की योजनाओं में हाथ बंटा सकें। इसका असर गांव के लोगों की सोच पर भी दिखने लगा है। टूटी सड़क अब सरकारी फाइल का विषय भर नहीं, बल्कि सबकी साझा जिम्मेदारी बन गई है। बंद पड़ी टंकी को गांव के लोग मिलकर फिर चालू कर

# श्रमदान से बदलती तस्वीर



सकते हैं। खाली पड़ी जमीन पौधरोपण का अवसर बन गई है। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, जिसके लिए पहले बजट का इंतजार होता था। 28 वर्षीय पूर्णा कहते हैं कि जब लोग किसी समस्या पर मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें उस जगह से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता

है, जिसे वे अपना घर कहते हैं।

बारिश के बाद सड़क चलने लायक बची है या नहीं, टंकी साफ है या नहीं, नाली बह रही है या नहीं, लगाए गए पौधों की देखभाल हो रही है या नहीं, तालाबों की सफाई हुई है या नहीं, ऐसी छोटी बातें भी उतनी ही मायने रखती

# नईदुनिया

# एयरपोर्ट पर मिसाइल और वैश्विक सुरक्षा का दूटता भ्रम

# तेरह मौतों के पीछे केवल हूती नहीं, पूरी व्यवस्था की विफलता

### रियाद

रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर एक सप्ताह में तीसरी बार मिसाइल गिरना केवल सऊदी अरब की समस्या नहीं है। यह उस सोच की हार है, जो मानती थी कि राजधानी सुरक्षित है, एयरपोर्ट सुरक्षित है और आम नागरिक युद्ध से दूर है। एक भारतीय समेत तेरह लोगों की मौत और 309 लोगों का घायल होना महज आंकड़ा नहीं, चेतावनी है कि युद्ध अब सीमा पर नहीं होता। वह लार्डज में होता है, रनवे पर होता है और उस जगह होता है, जहां आम आदमी अपने परिवार से मिलने के लिए इंतजार कर रहा होता है।

हूती विद्रोहियों ने हमला किया, सऊदी अरब ने जवाब दिया और अमेरिका ने विचार किया, लेकिन हूती जैसे समूह के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल कहां से आई कि वह यमन से रियाद तक मार कर सके, वह भी एक सप्ताह में तीन बार? इसका उत्तर केवल हथियारों में नहीं, बल्कि समर्थन, प्रशिक्षण और उस भू-राजनीति में है, जहां हर संघर्ष के पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी होती है। पहले युद्ध में किले निशाने पर होते थे, फिर तेल के कुएं निशाने पर आए और अब एयरपोर्ट निशाने पर हैं, क्योंकि एयरपोर्ट किसी भी देश की आर्थिक नब्ब है। रियाद एयरपोर्ट बंद होने से केवल उड़ानें नहीं रुकतीं, सऊदी अरब की साख और निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित होता है। हज और उमराह की व्यवस्था डगमगाती है।

हूती प्रवक्ता याह्या सरी का यह कहना कि मक्का-मदीना को छोड़ सभी एयरपोर्ट निशाने पर हैं, एक सोची-समझी चाल है। वह एक तरफ मुस्लिम भावनाओं को छू रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला कर रहे हैं। आधुनिक संघर्ष में धर्म और अर्थव्यवस्था, दोनों को हथियार बनाया जा रहा है। मक्का-मदीना को छोड़ने की बात कहकर हूती खुद को इस्लाम का रक्षक दिखाना चाहते हैं, जबकि बाकी एयरपोर्ट पर हमले करके सऊदी शासन को अस्थिर दिखाना चाहते हैं। यह दोहरी

# मानवता के अंत की पटकथा एआई लिखेगा लैंसेट की चेतावनी, सदी के अंत तक खतरे में हो सकती है सभ्यता

### ब्रिटेन

के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट से जुड़ी एक रिपोर्ट ने दुनिया के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान मानवता के सामने खड़े गंभीर खतरों की ओर खींचा है। रिपोर्ट में इक्कीसवीं सदी के वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी खतरों का विश्लेषण करते हुए चेताया गया है कि इस सदी के अंत तक मानव सभ्यता का अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), परमाणु युद्ध, जैविक हथियार, जलवायु परिवर्तन, महाभारियां और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गिरावट जैसे खतरे मानवता के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

सवाल यह है कि क्या ईसान अपनी ही बनाई तकनीक और हथियारों का शिकार बन जाएगा?

एआई को अब तक विकास और प्राति का प्रतीक माना जाता रहा है। चिकित्सा में यह बीमारियों की पहचान, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने और शिक्षा को सुलभ बनाने में मदद कर रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग गंभीर खतरे भी पैदा कर सकता है। जैविक हथियारों के विकास में एआई का इस्तेमाल ऐसी कारिकाओं को जन्म देता है, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिस तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, वही गलत हाथों में विनाश का साधन बन सकती है। इसलिए एआई के विकास के साथ उसके सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की व्यवस्था भी जरूरी है।

परमाणु युद्ध का खतरा भी कम भयावह नहीं है। बड़े पैमाने पर परमाणु संघर्ष होने पर विस्फोटों से होने वाली तबाही के अलावा वायुमंडल में धुआं और राख फैलने से सूर्य की रोशनी धरती तक कम पहुंच सकती है। इससे वैश्विक तापमान में गिरावट, कृषि उत्पादन में कमी और खाद्य संकट पैदा होने की आशंका है। इसका असर केवल युद्ध में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भुखमरी का संकट पैदा हो सकता है।

जैविक हथियारों का खतरा इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि संक्रामक रोग सीमाओं में बंधकर नहीं रहते। कोरोना महामारी ने दिखाया कि एक संक्रमण किस तरह पूरी दुनिया की स्वास्थ्य



व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। एआई के दुरुपयोग से जैविक खतरों को बढ़ावा मिलने की आशंका अंतरराष्ट्रीय निगरानी और सहयोग को और महत्वपूर्ण बनाती है।

इन खतरों के साथ जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, कुपोषण और महाभारियां भी मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। धरती का बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं जीवन को प्रभावित कर रही हैं। वायु प्रदूषण भी दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इन समस्याओं से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब देश आपसी अविश्वास और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहेंगे, तब वैश्विक समस्याओं का साझा समाधान निकालना कठिन होगा।

इसलिए एआई के नियमन, परमाणु निरस्त्रीकरण, जैविक हथियारों की रोकथाम और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वैज्ञानिक चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए सरकारों को पर्याप्त संसाधन और प्रभावी नीतियां सुनिश्चित करनी होंगी। मानवता का भविष्य आज लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर है। यह तय करना हमारे हाथ में है कि तकनीक का इस्तेमाल विनाश के लिए होगा या जनकल्याण के लिए। यदि दुनिया ने समय रहते इन खतरों से निपटने के लिए साझा प्रयास नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने कहीं अधिक असुरक्षित भविष्य होगा।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

### मक्का-मदीना को छोड़ सभी निशाने पर, इस वाक्य का गहरा अर्थ



रणनीति है, जो केवल मिसाइल से नहीं, संदेश से भी लड़ी जा रही है। सऊदी समर्थित यमन सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे में 1,150 हूती मारे गए हैं। यह आंकड़ा सच हो या प्रचार, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी युद्ध तेज हो सकता है। इसका असर लाल सागर पर पड़ेगा। लाल सागर से दुनिया का लगभग 12 प्रतिशत व्यापार गुजरता है। यदि वहां झोन और मिसाइल हमले बढ़े तो तेल, परिवहन और बीमा महंगे होंगे, जिसका बोझ अंततः आम भारतीय की जेब पर पड़ेगा। टैंकरों पर हमलों में दो भारतीय नाविकों का लापता होना इस बात का संकेत है कि यह युद्ध दूर का नहीं रह गया है। पहले होर्मुज जलडमरूमध्य में एमटी वाल्थेरा पर हमला हुआ, फिर ओमान के सोहार में एमटी पेद्रो डॉल्फिन पर झोन हमला हुआ। दोनों घटनाओं में भारतीय नाविक सवार हैं। यानी समुद्र भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि

अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है, स्थिति को शांत करने के बजाय और भड़का सकता है। इतिहास गवाह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने कई बार संघर्ष को लंबा किया है। ईरान हूतियों का समर्थक है और अमेरिका सऊदी अरब का सहयोगी। यदि दोनों आमने-सामने आए तो यह यमन का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है।

भारत के लिए यह कठिन स्थिति होगी, क्योंकि उसके संबंध ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका, तीनों से हैं। भारत किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन अपने नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए निष्क्रिय भी नहीं रह सकता। विदेश मंत्रालय ने हमले को अस्वीकार्य बताया है। यह जरूरी है, कि हमले पर्याप्त नहीं। सऊदी अरब में लाखों भारतीय काम करते

# अल नीनो अब समुद्र की लहर नहीं, स्वास्थ की लकीर है ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने कहा, चेतावनी बचा सकती है जान

### जब प्रशांत गर्म होता है तो भोपाल में लू क्यों बढ़ती है

महासागर के एक कोने में पानी का तापमान एक डिग्री बढ़ता है और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के एक गांव में किसान की फसल, मजदूर की लू से मौत और बच्चे के कुपोषण पर पड़ता है। इसी कड़ी को समझने के लिए ब्रिटेन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण शोध किया है। उनका कहना है कि अल नीनो और ला नीना अब केवल जलवायु संबंधी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। समय रहते पूर्व चेतावनी पर काम किया जाए तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि अल नीनो के चक्र का पूर्वानुमान महीनों पहले लगाया जा सकता है, लेकिन दुनिया तैयारी तब करती है, जब नुकसान हो चुका होता है। इसलिए उन्होंने चरम गर्मी से निपटने और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पांच प्रमुख उपाय सुझाए हैं। अक्सर हम अल नीनो को केवल गर्मी से जोड़ते हैं, लेकिन इसका असर कहीं अधिक व्यापक है। अत्यधिक गर्मी से शरीर में पानी की कमी, लू लगने और हृदय पर दबाव बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं, बाढ़ और तापमान में बदलाव से मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी बीमारियों का प्रसार तेज हो सकता है। फसल कमजोर होने से खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, जिसका सीधा असर बच्चों के पोषण पर पड़ता है। यानी समुद्र में होने वाला बदलाव पूरे स्वास्थ्य तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्से भी अल नीनो के प्रभावों का सामना करते हैं। भारत में इसका संबंध मानसून से है। अल नीनो के सक्रिय होने पर मानसून कमजोर पड़ सकता है। इससे खेत सूखते हैं, पेयजल संकट गहराता है, बिजली की मांग बढ़ती है और लू से होने वाली मौतों का खतरा बढ़ जाता है।

शोधकर्ताओं के सुझाए पांच उपायों का सार एक ही है: चेतावनी को प्रयोगशाला से निकालकर पंचायत तक पहुंचाना। हर देश अपने जीविम का नक्शा बनाए, ताकि पता चल सके कि किस जिले में गर्मी, बाढ़ और बीमारियों का खतरा सबसे अधिक है। पूर्व चेतावनी

हैं। उनके लिए रियाद एयरपोर्ट केवल हवाई अड्डा नहीं, घर लौटने का दरवाजा है। उड़ानें रद्द होने से उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। भारत को कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए और क्षेत्रीय तनाव कम कराने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

इस हमले ने विमानन सुरक्षा की पूरी अवधारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक एयरपोर्ट के भीतर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन खतरा बाहर से आने वाली मिसाइलों का भी है। इसका अर्थ है कि एयरपोर्ट सुरक्षा को व्यापक बनाना होगा। सऊदी अरब के पास पैट्रियट जैसी वायु रक्षा प्रणालियां हैं, फिर भी खतरे का बने रहना बताता है कि तकनीक भी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

पहले युद्ध में सेना लड़ती थी, अब एयरपोर्ट पर बैठा यात्री मारा जाता है। पहले सीमा पर गोली चलती थी, अब समुद्र में टैंकर जलते हैं। पहले युद्ध दो देशों के बीच सीमित रहता था, अब एक विद्रोही समूह भी राजधानी और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। रियाद पर हमला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और कोई भी संघर्ष केवल स्थानीय नहीं रह गया है।

इस हमले को केवल तेरह मौतों की खबर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उस बदलती विश्व व्यवस्था की चेतावनी है, जहां एयरपोर्ट युद्ध का मैदान बन रहे हैं, नाविक संघर्ष के शिकार हो रहे हैं और आम भारतीय भी इसकी कीमत चुका रहा है, चाहे वह रियाद में हो या मुंबई में। यदि समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो मक्का-मदीना को छोड़ सभी एयरपोर्ट निशाने पर होने की धमकी केवल सऊदी अरब नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )



प्रणाली को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाए। मौसम विभाग अगले पंद्रह दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी दे तो अस्पतालों में दवाओं की तैयारी हो, आंगनबाड़ियों में पानी और ओआरएस उपलब्ध हों। जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त शोध बढ़े तथा प्रभावित समूहों की लगातार निगरानी की जाए। कम लागत वाले प्रभावी उपाय अपनाए जाएं, जैसे लू से बचाव के लिए मजदूरों के काम के समय में बदलाव और खाद्य आपूर्ति को मजबूत करना।

हमारे पास उपग्रह हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन तैयारी की कमी है। हम अल नीनो का पूर्वानुमान तो लगा लेते हैं, लेकिन उसे आशा कार्यकर्ता और किसान तक नहीं पहुंचाते। अल नीनो को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रभावों को कम करना संभव है। यदि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर योजना बनाएं, स्कूलों में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो और मनरेगा के काम सुबह जल्दी तथा शाम को कराए जाएं, तो कई जानें बचाई जा सकती हैं।

अल नीनो हमें सिखा रहा है कि समुद्र और शरीर, जलवायु और स्वास्थ्य अलग-अलग नहीं हैं। प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने का असर भोपाल में किसी बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन को केवल कृषि की खबर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की चेतावनी मानना होगा। समय रहते कदम उठाना ही इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

का सबसे बड़ा संसाधन पैसा नहीं, बल्कि लोगों की एकजुटता है। तेलंगाना का यह प्रयोग अब धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन रहा है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ गांवों में भी इसी तरह के प्रयास शुरू हुए हैं, जहां ग्रामीणों ने महीने में एक दिन श्रमदान करने का संकल्प लिया है। यह केवल सड़क या तालाब बनाने का अभियान नहीं, बल्कि गांव को फिर से अपना बनाने का अभियान है।

आने वाले समय में जरूरत इस बात की है कि ऐसे प्रयासों को सम्मान मिले, पंचायत स्तर पर मान्यता मिले और इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। यदि मनरेगा जैसी योजनाओं को श्रमदान के साथ समन्वित किया जाए, तो गांवों की तस्वीर और तेजी से बदल सकती है। लक्काराम गांव की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत के गांवों की असली ताकत उनके लोग हैं। जब लोग एक साथ आते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है और जब लोग बंट जाते हैं, तो छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि श्रमदान जैसी परंपराओं को फिर से जीवित किया जाए और गांवों को मजबूत बनाया जाए।

यह केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है, जो अपने गांवों से बनता है। यदि हर गांव महीने में एक दिन श्रमदान के लिए निकाले, तो देश के हजारों गांवों की तस्वीर बदल सकती है। यही सच्चा विकास होगा, जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )